

ment's consideration to relate the cost of production with the price of wheat for Maharashtra as has been requested for by the Maharashtra Government?]

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : समर्थन मूल्य का निर्धारण करते समय उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए अलग से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। गेहूँ का जो वसूली मूल्य निर्धारित किया जाएगा वह समूचे देश के लिए होगा।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): Cost of production is taken into consideration in fixation of support prices. But no separate decision can be taken for Maharashtra. Procurement price of wheat that will be fixed will be for the whole country.]

Stay of Section 32(B) of the Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948

147. SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to refer to answer to unstarred question No. 1162 given in the Rajya Sabha on the 2nd August, 1978 and state:

(a) whether Gujarat Government have completed their examination of the issue regarding the contents and implication of the State Government's orders staying in operation of section 32(B) of the Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948; and

(b) if so, what are the details thereof and what decision Government have taken in this matter?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The Gujarat Government have not yet completed their examination of the issue.

(b) Does not arise.

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास संबंधी समिति

148. श्री हरिशंकर भाभड़ा :

श्री कलराज मिश्र :

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने को तैयार करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी तथा अन्य संसाधनों का पता लगाने के लिए श्री एल० सी० जैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) क्या सरकार को समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

Committee on development of rural areas

148. SHRI HARISHANKAR BHABHRA: SHRI KALRAJ MISHRA: SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Committee was appointed under the chairmanship of Shri L. C. Jain to explore the technology and other resources for the development of rural areas;

(b) whether Government have received the report of the Committee; and

(c) if so, what are the recommendations of the Committee and what action Government have taken thereon?]

[] English translation.

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जो हूँ, उपर्युक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का पता लगाने तथा उनको तेजी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए श्री एल० सी० जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी ।

(ख) रिपोर्ट को योजना आयोग को उनकी सहमति हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(ग) जैन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अनुसंधान के समन्वय तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव किया है । इस केन्द्र का उद्देश्य है उपर्युक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने तथा उनको तेजी के साथ विशेषकर निर्धनों में भी निर्यततम तक पहुंचाने के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करना ।

इस समिति की सिफारिशों के अनुसार यह केन्द्र शुरू में निम्नलिखित कार्यों पर बल देगा :—

(i) ग्रामीण प्रौद्योगिकी को उस प्रकार की उपलब्ध सामग्रों पर सूचना को एकत्रित करना तथा उसे फैलाना जिसका उपयोग, विवेचनात्मक लागत-लाभ विश्लेषण के आधार पर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकीय और सामाजिक आर्थिक दशाओं के अन्तर्गत किया जा सके ;

(ii) उन बड़े कमियों का पता लगाना जो ग्रामीण प्रौद्योगिकी में विद्यमान हों और इन कमियों को दूर करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों का प्रोत्साहित करना ;

(iii) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी क्रियाविधि में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान करने वाले संस्थानों तथा क्षेत्र अभिकरणों के बीच एक सम्पर्क निर्माण करना ;

(iv) सक्षम एजेंसियों के माध्यम से विकास संबंधी तुलन-पत्र (वैलेन्स शीट) तैयार करने, विकास खण्ड की योजना बनाने की क्रियाविधि, फसल-उत्पादन की समाकलित पद्धतियों का विकास और फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठित करना ; और

(v) समाकलित ग्रामीण विकास के हित में युवा व्यवसायियों से एक ग्रामीण स्रोत दल संगठित करना ।

[THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes Sir, a Committee was constituted under the Chairmanship of Shri L. C. Jain with a view to consider the question of identifying appropriate rural technologies and their speedy transfer to the rural areas.

(b) The report has been submitted to the Planning Commission for their concurrence.

(c) Based on the recommendation of the Jain Committee, the ICAR has developed a proposal for the establishment of a national Centre for Co-ordination of Research and Transfer of Rural Technology. This Centre intends to serve as a catalytic agent in evolving appropriate rural technologies and their rapid transfer specially to the poorest of the poor.

As per recommendations of the Committee, the Centre, to start with, will concentrate on the following functions:

[] English translation.

(i) Collecting and spreading information on the available fund of rural technology that could be applied under wide-ranging ecological and socio-economic conditions in rural and tribal areas on the basis of a critical cost-benefit analysis;

(ii) identifying critical gaps that exist in the rural technology and encouraging efforts both official and non-official to cover these gaps;

(iii) providing a link between institutions conducting research on rural technology as well as field agencies both official and non-official working in the field of rural development;

(iv) organising training programmes through competent agencies for the preparation of developmental balance sheets, methodology for block planning, and development of integrated systems of crop production, post-harvest technology etc.; and

(v) organising a Rural Resource Crops of young professionals in the interest of integrated rural development.]

उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूँ के मूल्य में वृद्धि

149. श्री हरिशंकर भाभड़ा :

श्री कलराज मिश्र :

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्रो यह बताने को उपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले गेहूँ का मूल्य दिसम्बर, 1978 में बढ़ा दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ तो मूल्य में कितनी वृद्धि की गई और उसके क्या कारण हैं?

Increase In price of wheat at the fair price shops

149. SHRI HARI SHANKAR

BHABHRA: SHRI KALIRAJ

MISHRA: SHRI JAGDISH

PRASHAD MATHUR:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased state:

(a) whether it is a fact that the price of wheat sold to consumers at the fair price shops was increased in December, 1978; and

(b) if so, the extent of increase in the price and the reasons therefor?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जो हाँ।

(ख) केन्द्रीय निर्गम मूल्य में 5 रुपये की वृद्धि की गई थी ताकि गेहूँ और चावल पर राजसहायता के समूचे भार को युक्ति-युक्त किया जा सके।

[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Yest, Sir.

(b) The Central issue Price was increased by Rs. 5 per quintal, in order the rationalise the overall burden of subsidy on wheat and rice.]

Takeover of Sugar Mills

150. SHRI M. ANANDAM: SHRI JAHARLAL BANERJEE: SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: SHRI A. G. KULKARNI:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) what is the number of private co-operative sugar factories which

[] English translation.